IGNOU "MOTHER PUBLICATION" All PDF BUY ON WHATSAPP MSG- 9485943709
Page 1 of 38 Pages in this Full pdf
THIS IS COPYRIGHT PDF DO NOT SELL OR SHARE TO ANYONE- OTHERWISE LEGAL ACTION TAKEN

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

एमपीएसई-011

(हिन्दी माध्यम)

FROM PREVIOUS YEAR PAPER's

IMPORTANT QUESTION ANSWER's

Guess Paper / Exam Notes

By India's No.1 - Mother Publication

FOR MORE PDF 9485943709

Disclaimer for Guess / Sample Paper By MOTHER NOTES- 8529719732, 99922-90905: -

This PDF contains sample papers compiled from previous years' questions of the IGNOU It is intended to provide you with a general idea of the paper format and may cover some potential questions. However, it is important to note the following:

1. **No Guarantee of Exam Questions:** We do not guarantee that the questions presented in this sample paper will appear in your actual exams. The content is for practice purposes only.
2. **Book Study Recommended:** To achieve good marks in your IGNOU exams, it is highly recommended that you thoroughly study the prescribed course materials and textbooks. Relying solely on this sample paper may not be sufficient for exam success.
3. **Use as a Study Aid:** Use this sample paper as a supplementary study aid to test your knowledge and exam preparedness.
4. **Self-Responsibility:** Your performance in exams is your responsibility, and success depends on your dedication to studying the course material.

We wish you the best of luck with your IGNOU exams. Thank you for using this sample paper as part of your preparation. **By MOTHER NOTES- 8529719732, 99922-90905**

All Full PDF- https://mothernotes.in/ - Previous year solved paper , Guess Paper.

IGNOU "MOTHER PUBLICATION" All PDF BUY ON WHATSAPP MSG- 9485943709
Page 2 of 38 Pages in this Full pdf
THIS IS COPYRIGHT PDF DO NOT SELL OR SHARE TO ANYONE- OTHERWISE LEGAL ACTION TAKEN

खंड-I

10 अंकों के प्रश्न - प्रत्येक 400-500 शब्द

प्रश्न - यूरोपीय एकीकरण के अध्ययन के लिए संघीय, अंतर-सरकारी और सह-संघीय दृष्टिकोणों के बीच अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर- **यूरोपीय एकीकरण के लिए संघीय, अंतर-सरकारी और सह-संघीय दृष्टिकोण**

यूरोपीय एकीकरण का विश्लेषण विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों, मुख्यतः **संघीय, अंतर-सरकारी और सह-संगठनात्मक दृष्टिकोणों के माध्यम से किया गया है** । ये दृष्टिकोण संप्रभुता, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और राजनीतिक एकीकरण की गहराई की अपनी समझ में भिन्न हैं।

1. संघीय दृष्टिकोण

संघीय दृष्टिकोण यूरोपीय एकीकरण को संघीय राज्य के निर्माण के समान **क्रमिक राजनीतिक एकीकरण** की एक प्रक्रिया के रूप में देखता है । अर्न्स्ट बी. हास और लियोन लिंडबर्ग जैसे विद्वानों ने **नव-कार्यात्मकता पर जोर दिया** , जो बताता है कि आर्थिक और कार्यात्मक क्षेत्रों (जैसे व्यापार, ऊर्जा या परिवहन) में एकीकरण राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण में बदल जाएगा। संघवादी दृष्टिकोण यूरोपीय आयोग और यूरोपीय न्यायालय जैसी **सुपरनैचुरल संस्थाओं को धीरे-धीरे सदस्य राज्यों पर अधिकार प्राप्त करने की वकालत करता है। यहाँ, एक साझा यूरोपीय पहचान बनाने** और राष्ट्र-राज्यों से आम यूरोपीय निकायों को संप्रभुता हस्तांतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अंतिम लक्ष्य **यूरोप का एक संघ है** , जहाँ निर्णय सामूहिक रूप से सुपरनैचुरल स्तर पर लिए जाते हैं, न कि केवल राष्ट्रीय सरकारों द्वारा।

2. अंतर-सरकारी दृष्टिकोण

: दूसरी ओर, अंतर-सरकारी दृष्टिकोण सदस्य देशों के बीच **राज्य संप्रभुता और स्वैच्छिक सहयोग पर ज़ोर देता है। स्टेनली हॉफमैन जैसे विद्वानों का तर्क है कि यूरोपीय एकीकरण शक्तिशाली देशों के राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है** , और निर्णय मुख्य रूप से अंतर-सरकारी स्तर पर, जैसे कि यूरोपीय परिषद में, बातचीत और आम सहमति के माध्यम से होता है। सुपरनेशनल संस्थाओं के अधिकार सीमित होते हैं, जो निर्णय लेने वालों के बजाय केवल सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। यह दृष्टिकोण इस बात पर प्रकाश डालता है कि **एकीकरण** एक यूरोपीय संघीय राज्य की ओर एक

FOR MORE PDF 9485943709

All Full PDF- https://mothernotes.in/ - Previous year solved paper , Guess Paper.

IGNOU "MOTHER PUBLICATION" All PDF BUY ON WHATSAPP MSG- 9485943709
Page 3 of 38 Pages in this Full pdf
THIS IS COPYRIGHT PDF DO NOT SELL OR SHARE TO ANYONE- OTHERWISE LEGAL ACTION TAKEN

कदम के बजाय कूटनीति का एक साधन है। सदस्य देश रक्षा, विदेश नीति और आर्थिक निर्णयों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, और केवल तभी सहयोग करने पर सहमत होते हैं जब यह उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता हो।

3. सह-सहयोगात्मक दृष्टिकोण

सह -सहयोगात्मक दृष्टिकोण **बहु-जातीय या बहु-राष्ट्रीय परिवेशों में विविधता के प्रबंधन** पर केंद्रित है । यूरोपीय एकीकरण पर लागू, एरेंड जैसे विद्वान लिजफार्ट **सत्ता-साझेदारी, गठबंधन-निर्माण और संस्थागत तंत्रों** पर ज़ोर देते हैं जो सभी महत्वपूर्ण समूहों या राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। यूरोप को विभिन्न प्राथमिकताओं वाले **राज्यों के एक जटिल नेटवर्क के रूप में देखा जाता है** , जिसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक बातचीत, समझौते और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। एकीकरण का अर्थ संप्रभुता का हस्तांतरण या संघ का गठन नहीं है, बल्कि **ऐसी सहकारी व्यवस्थाएँ बनाना है जो विविधता को समायोजित करें** और किसी एक राज्य या समूह के प्रभुत्व को रोकें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, **संघीय दृष्टिकोण** अतिराष्ट्रवाद और अंततः राजनीतिक एकीकरण पर ज़ोर देता है , **अंतर-सरकारी दृष्टिकोण** राज्य संप्रभुता और बातचीत के ज़रिए सहयोग पर ज़ोर देता है, जबकि **सह-सहयोगी दृष्टिकोण** विविधता को प्रबंधित करने के लिए समावेशी, सत्ता-साझाकरण व्यवस्था पर ज़ोर देता है। ये सभी दृष्टिकोण मिलकर यूरोपीय एकीकरण की गतिशीलता और जटिलताओं के बारे में पूरक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

प्रश्न - यूरोपीय संघ की भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह यूरोपीय संघ की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होगा?

उत्तर- अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, राजनीतिक सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित यूरोपीय संघ (ईयू) अपनी स्थापना के बाद से महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुज़रा है। आज, यूरोपीय संघ के सामने अवसर और चुनौतियाँ दोनों हैं जो इसके भविष्य की संभावनाओं को आकार देंगे। इन कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण यह समझने में मदद करता है कि क्या यह अपने नागरिकों और हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है।

आर्थिक रूप से, यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे बड़े एकल बाजारों में से एक बना हुआ है, जो सदस्य देशों को एक विशाल आंतरिक बाजार तक पहुँच प्रदान करता है, व्यापार को सुगम बनाता है और निवेश को प्रोत्साहित करता है। यूरोपीय ग्रीन डील और डिजिटल परिवर्तन रणनीतियाँ जैसी पहल सतत विकास और तकनीकी उन्नति के प्रति संघ की प्रतिबद्धता का संकेत देती हैं। हालाँकि, सदस्य देशों के बीच, विशेष रूप से उत्तरी और दक्षिणी यूरोप के बीच, आर्थिक असमानताएँ गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। कुछ क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी, आर्थिक विकास में ठहराव और राजकोषीय असहमति जैसे स्थायी मुद्दे यूरोपीय संघ की एकसमान समृद्धि प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करते हैं।

राजनीतिक रूप से, यूरोपीय संघ राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए एकता बनाए रखने की आकांक्षा रखता है। संघ ने ब्रेक्सिट संक्रमण जैसे जटिल मुद्दों को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है और कोविड-19 महामारी जैसे वैश्विक संकटों के लिए समन्वित प्रतिक्रियाएँ दी हैं। फिर भी, बढ़ता राष्ट्रवाद, यूरो-संदेहवाद और कई सदस्य देशों में राजनीतिक विखंडन एकजुटता के लिए ख़तरा है। चुनौती अलग-अलग देशों की विविध राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ गहन एकीकरण को संतुलित करने में है, जो एक ऐसा कार्य है जो लगातार जटिल होता जा रहा है।

सामाजिक रूप से, यूरोपीय संघ का लक्ष्य पूरे महाद्वीप में समावेशिता, मानवाधिकार और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है। गतिशीलता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम इन आदर्शों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। फिर भी, प्रवासन संकट, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सामाजिक असमानता यूरोपीय संघ की अपनी सामाजिक आकांक्षाओं को निरंतर बनाए रखने की क्षमता की परीक्षा लेते हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए नवीन नीतियों और राज्यों के बीच मज़बूत सहयोग की आवश्यकता है, जो हमेशा संभव नहीं होता।

अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, यूरोपीय संघ खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, व्यापार, जलवायु नीतियों और राजनयिक संबंधों को प्रभावित करना चाहता है। हालाँकि इसने रणनीतिक साझेदारियों पर सफलतापूर्वक बातचीत की है, लेकिन चीन जैसी उभरती शक्तियों से वैश्विक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय संघर्ष इसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए बाहरी चुनौतियाँ पेश करते हैं।

निष्कर्षतः, यूरोपीय संघ का भविष्य आशा और अनिश्चितता का मिश्रण है। हालाँकि इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और वैश्विक प्रभाव को बढ़ावा देने की क्षमता है, लेकिन आंतरिक विभाजन, आर्थिक असमानताएँ और राजनीतिक विखंडन इसकी आकांक्षाओं को पूरी तरह साकार करने की क्षमता को सीमित करते हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संघ राष्ट्रीय पहचान से समझौता किए बिना एकीकरण को गहरा करने,

FOR MORE PDF-9485943709

All Full PDF- https://mothernotes.in/ - Previous year solved paper , Guess Paper.

IGNOU "MOTHER PUBLICATION" All PDF BUY ON WHATSAPP MSG- 9485943709
Page 4 of 38 Pages in this Full pdf
THIS IS COPYRIGHT PDF DO NOT SELL OR SHARE TO ANYONE- OTHERWISE LEGAL ACTION TAKEN

संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने और वैश्विक चुनौतियों के अनुकूल ढलने की क्षमता रखता है। यूरोपीय संघ के आगे के मार्ग के लिए न केवल दूरदर्शी नीतियों की आवश्यकता होगी, बल्कि निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनता के विश्वास की भी आवश्यकता होगी।

ALL SOLVED ASSIGNMENT, GUESS PAPER, PROJECT - HAND WRITTEN SCAN PDF, HARDCOPY BY POST ORDER- ON WHATSAPP MSG- 8529719732, 99922-90905 OR VISIT- motherpublication.in / mothernotes.in

प्रश्न - यूरोपीय संघ संवैधानिक संधि के मुख्य प्रावधानों की संक्षेप में व्याख्या करें।

उत्तर- **यूरोपीय संघ संवैधानिक संधि के मुख्य प्रावधान**

यूरोपीय **संघ (ईयू) संवैधानिक संधि** , जिसे यूरोप के लिए संविधान स्थापित करने वाली संधि के रूप में भी जाना जाता है, पर 2004 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के संचालन को सुव्यवस्थित करना, इसकी संरचना को स्पष्ट करना और इसकी लोकतांत्रिक वैधता को बढ़ाना था। हालाँकि फ्रांस और नीदरलैंड में जनमत संग्रह में अस्वीकृति के कारण इसे कभी भी पूरी तरह से अनुमोदित नहीं किया गया था, लेकिन इसके प्रावधानों ने बाद की संधियों, जैसे **लिस्बन संधि , को प्रभावित किया** । संवैधानिक संधि के मुख्य प्रावधानों को निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में संक्षेपित किया जा सकता है:

1. संस्थागत सुधार

इस संधि का उद्देश्य यूरोपीय संघ के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना और दक्षता में सुधार करना था। इसने सदस्य देशों के बीच सुसंगत नेतृत्व और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए **यूरोपीय परिषद के एक स्थायी अध्यक्ष का प्रस्ताव रखा। सभी सदस्य देशों का अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय आयोग का पुनर्गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, इस संधि ने यूरोपीय संसद की भूमिका को** बढ़ाया , सह-निर्णय प्रक्रियाओं के माध्यम से उसे अधिक विधायी शक्ति प्रदान की, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही मजबूत हुई।

2. कानूनी व्यक्तित्व

इस संधि ने यूरोपीय संघ को एक **एकल कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया** , जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने और एक एकीकृत इकाई के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने का अधिकार मिला। इस प्रावधान का उद्देश्य वैश्विक मामलों में यूरोपीय संघ की स्थिति को स्पष्ट करना और उसके बाहरी संबंधों को सुव्यवस्थित करना था।

3. मौलिक अधिकारों का चार्टर

संधि के महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक **मौलिक अधिकारों के चार्टर** को यूरोपीय संघ के कानून में शामिल करना था, जिससे मानव गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और एकजुटता जैसे सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गए। इस प्रावधान का उद्देश्य सभी सदस्य देशों के नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देना और सामाजिक एवं राजनीतिक सामंजस्य को बढ़ाना था।

4. संधियों का सरलीकरण

इस संधि में मौजूदा यूरोपीय संघ की संधियों को एक **एकल, सुसंगत पाठ में समेकित करने का प्रस्ताव था** , जो कई मूलभूत संधियों का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य कानूनी जटिलता को कम करना, पारदर्शिता में सुधार करना और यूरोपीय संघ को अपने नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना था।

5. निर्णय लेना और मतदान

संधि ने **दक्षता बढ़ाने के लिए मतदान नियमों में बदलाव किए** , जिसमें मंत्रिपरिषद में अधिक नीतिगत क्षेत्रों के लिए **योग्य बहुमत से मतदान शामिल है, जिससे सर्वसम्मति की आवश्यकता कम हो गई। इस सुधार का उद्देश्य बड़े और छोटे राज्यों के प्रभाव को संतुलित करते हुए निर्णय लेने की गति बढ़ाना था।**

6. विदेश नीति और सुरक्षा

FOR MORE PDF-9485943709

All Full PDF- https://mothernotes.in/ - Previous year solved paper , Guess Paper.

IGNOU "MOTHER PUBLICATION" All PDF BUY ON WHATSAPP MSG- 9485943709
Page 5 of 38 Pages in this Full pdf
THIS IS COPYRIGHT PDF DO NOT SELL OR SHARE TO ANYONE- OTHERWISE LEGAL ACTION TAKEN

विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए एक उच्च प्रतिनिधि की स्थापना करके यूरोपीय संघ की **सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति (सीएफएसपी) को मजबूत किया** , जो यूरोपीय संघ का बाहरी रूप से प्रतिनिधित्व करेगा और इसके राजनयिक कार्यों का समन्वय करेगा, जिससे वैश्विक मंच पर सुसंगतता और दृश्यता बढ़ेगी।

7. सहायकता और नागरिक भागीदारी

सहायकता के सिद्धांत पर ज़ोर दिया , यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्णय यथासंभव नागरिकों के ध्यान में रखे जाएँ। इसने **नागरिक पहल की भी शुरुआत की** , जिसके तहत यूरोपीय संघ के नागरिकों को दस लाख हस्ताक्षरों के समर्थन से कानून प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। निष्कर्षत:, यूरोपीय संघ संवैधानिक संधि का उद्देश्य **यूरोपीय संघ के शासन को आधुनिक बनाना, नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करना, कानूनी संरचनाओं को सरल बनाना और निर्णय लेने में दक्षता में सुधार करना है** , जिससे एक अधिक एकजुट और प्रभावी यूरोपीय संघ के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जा सके।

प्रश्न - यूरोपीय संघ के पूर्व की ओर विस्तार के मुद्दों और निहितार्थों की जांच करें।

उत्तर- यूरोपीय संघ (ईयू) का पूर्व की ओर विस्तार उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से मध्य और पूर्वी यूरोप के देश, मुख्यतः 2004 और 2007 के प्रवेश दौरों के माध्यम से, यूरोपीय संघ में शामिल हुए। इस विस्तार का उद्देश्य साम्यवाद-उत्तर देशों को एक एकीकृत यूरोपीय ढाँचे में एकीकृत करना, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और एक व्यापक एकल बाज़ार को बढ़ावा देना था। हालाँकि इस कदम ने यूरोपीय संघ के ऐतिहासिक विस्तार को चिह्नित किया, लेकिन इसने कई जटिल मुद्दे और महत्वपूर्ण निहितार्थ भी लाए।

1. आर्थिक मुद्दे और चुनौतियाँ: मुख्य चिंताओं में से

एक नए सदस्य देशों और पुराने यूरोपीय संघ-15 देशों के बीच आर्थिक असमानता थी। कई पूर्वी यूरोपीय देशों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कम था, बुनियादी ढाँचा अविकसित था, और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएँ अभी भी केंद्रीय नियोजन से बाज़ार प्रणालियों के अनुकूल हो रही थीं। इससे श्रम गतिशीलता, प्रतिस्पर्धात्मकता और संरचनात्मक निधि आवंटन के संदर्भ में चुनौतियाँ पैदा हुईं। यूरोपीय संघ को विकास को समर्थन देने के लिए सामंजस्य निधि और संरचनात्मक निधि जैसी व्यवस्थाएँ स्थापित करनी पड़ीं, लेकिन आर्थिक असंतुलन के कारण कभी-कभी पुराने सदस्यों के साथ तनाव पैदा हो जाता था, जो संभावित श्रम प्रवास और वेतन दबावों को लेकर चिंतित थे।

2. राजनीतिक और संस्थागत मुद्दे:

पूर्व की ओर विस्तार के लिए यूरोपीय संघ के भीतर महत्वपूर्ण संस्थागत समायोजन आवश्यक थे। मंत्रिपरिषद और यूरोपीय संसद जैसे निर्णय लेने वाले ढाँचों में, सदस्य देशों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए सुधार की आवश्यकता थी। नए सदस्यों में भिन्न शासन मानकों, कानून के शासन और भ्रष्टाचार के स्तर को लेकर राजनीतिक चिंताएँ भी थीं। यूरोपीय संघ के मानदंडों और कोपेनहेगन मानदंडों (लोकतंत्र, कानून का शासन, मानवाधिकार और एक कार्यशील बाजार अर्थव्यवस्था) का अनुपालन सुनिश्चित करना, प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एक प्रमुख चुनौती बन गया।

3. सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थ:

इस विस्तार के गहरे सामाजिक निहितार्थ थे, खासकर प्रवासन और श्रम गतिशीलता के संबंध में। नए सदस्य देशों के नागरिकों को यूरोपीय संघ में काम करने और रहने का अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे पश्चिमी यूरोप में महत्वपूर्ण प्रवासन प्रवाह हुआ। इससे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में श्रम की कमी को पूरा करने में मदद मिली, लेकिन इससे सामाजिक तनाव, विदेशी-द्वेष और एकीकरण की चुनौतियाँ भी पैदा हुईं। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक अनुभवों में अंतर ने यूरोपीय संघ-व्यापी नीति-निर्माण और पहचान निर्माण में संभावित टकराव पैदा किया।

4. भू-राजनीतिक और सामरिक निहितार्थ:

सामरिक दृष्टि से , पूर्व की ओर विस्तार ने यूरोप में यूरोपीय संघ के प्रभाव को बढ़ाया और शीत युद्धोत्तर क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दिया। हालाँकि, इसने यूरोपीय संघ-रूस संबंधों को भी जटिल बना दिया, क्योंकि मास्को ने इस विस्तार को पूर्वी यूरोप में प्रभाव संतुलन में बदलाव के रूप में देखा। यूरोपीय संघ को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार और कूटनीतिक विचारों, विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति में, के बीच संतुलन बनाना पड़ा।

निष्कर्ष:

यूरोपीय संघ का पूर्व की ओर विस्तार एक अवसर और एक चुनौती दोनों का प्रतिनिधित्व करता था। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से,

FOR MORE PDF-9485943709

All Full PDF- https://mothernotes.in/ - Previous year solved paper , Guess Paper.

IGNOU MOTHER PUBLICATION - ASSIGNMENTS & GUESS PAPERS & PYQ SOLVED PDF

INDIA'S NUMBER 1 STUDY MATERIAL PROVIDER

यह केवल एक सैंपल पीडीएफ है।

यह केवल Sample PDF है। पूरी Solved Assignment या Guess Paper PDF खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ

या

WhatsApp पर मैसेज करें।

WHATSAPP ONLY: +91 9485943709

WHATSAPP ONLY:: +91 9992290905

1. Solved Assignment Visit -:: https://motherpublication.in/

2. Pyq Solved Guess paper Visit:-: https://mothernotes.in/

Mother Publication • IGNOU Study Resources